शुगर पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगने के आसार

[पीटीआई | नई दिल्ली]

चीनी की कीमतों में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 25 से बढ़ाकर 40 फीसदी कर सकती है। चीनी मिलों को करीब 20,000 करोड़ रुपये की रकम गन्ना किसानों को चुकानी है। मिलों को भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए भी सरकार यह कदम उठा सकती है।

फूड मिनिस्टर राम विलास पासवान की अगुवाई वाले मंत्रियों के अनौपचारिक ग्रुप की एक मीटिंग में मंगलवार को चीनी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की सिफारिश करने का फैसला किया गया। इसके अलावा, इस मीटिंग में किसानों और चीनी मिलों के सामने आए मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए बफर स्टॉक बनाने, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग, एथनॉल प्रॉडक्शन को प्रोत्साहन देने, व्हाइट शुगर पर एक्सपोर्ट सब्सिडी के अलावा कई दूसरे मुद्दों पर भी सहमति बनी।

फैसले का मकसद

- **चीनी मिलों** को करीब 20,000 करोड़ रुपये की रकम गन्ना किसानों को चुकानी है
- **मिलों को** भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए भी सरकार यह कदम उठा सकती है

मीटिंग के बाद पासवान ने कहा, गन्ने की बकाया रकम के जल्द भुगतान के लिए किसानों और राज्य सरकारों की ओर से दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। किसानों की तकलीफ और चीनी उद्योग के सामने खड़ी हुई स्थिति को देखते हुए कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनी है।

इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कुछ सुझावों को लागू करने के लिए कैबिनेट प्रपोजल्स को लाया जाएगा, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीनी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। नगदी संकट का सामना करने वाली शुगर इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने के लिए पिछले साल अगस्त में रॉ और रिफाइंड शुगर दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15 से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया था।

मीटिंग में पासवान के अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गड़करी, एग्रीकल्चर मंत्री राधा मोहन सिंह, कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीमारमण, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, विमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी मौजूद थे। पासवान ने गन्ने की बकाया रकम के संकट को सुलझाने के लिए 15-16 अप्रैल को किसानों और मुख्यमंत्रियों की दो अलग-अलग बैठकें बुलाईं थीं। शुगर इंडस्ट्री को प्रॉडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण उसे पिछले कुछ वर्षों से हो रहे घाटे के चलते किसानों को गन्ने के भुगतान में दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीनी मिलों की नगदी की स्थिति में सुधार लाने के लिए 14 लाख टन रॉ शुगर के एक्सपोर्ट के लिए 4,000 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी है। इस्मा की डिमांड है कि सरकार व्हाइट शुगर के एक्सपोर्ट पर भी सब्सिडी दे, 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाए और मिलों के 36,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करे।

इकनॉमिक टाइम्स
22/4/15